

सम्पादकीय

सरकार अनजान, जनता परेशान

तीन कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक संसद में पारित करवा कर केंद्र सरकार ने यह मान लिया था कि अब एक साल से आंदोलनरत किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन कानून वापसी के बावजूद किसानों की घर वापसी नहीं हुई, क्योंकि किसान एमएसपी पर गारंटी समेत कुछ और मार्गे सरकार से परी करवाना चाहते हैं। इनमें आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की मुआवजा और उनकी याद में स्मारक बनाना, जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें वापस लेने की मार्गे भी शामिल हैं। लोकसभा में कुछ सासदों ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का डेटा सरकार से जानना चाहा, साथ ही ये पृष्ठा कि क्या सरकार का उक्त आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को संसद में बताया है कि सरकार के पास दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विषय की ओर से मृतक किसानों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चूंकि सरकार के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में आर्थिक सहायता देने का सवाल ही नहीं उठता। मानवीय स्वभाव है कि जब आप किसी के बारे में फिक्रमंद होते हैं, किसी का भला चाहते हैं तो उसका सुख, उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता होती है। आप ये जानने की कोशश करते हैं कि उसके जीवन में कोई मुश्किल तो नहीं है, वो अगर किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो उस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में विचार किया जाता है। न कि ये कहा जाता है कि मैं तुम्हारा हैतीषी तो हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि तुमने कौन सी तकलीफें उठाई हैं, इसलिए मैं उन तकलीफों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बक्त भोवी सरकार का किसानों के लिए रवया कुछ इसी तरह का है।

कृषि मंत्री ने कितनी आसानी से संसद में यह जवाब दे दिया कि सरकार के पास किसानों की मौत का कोई रिकार्ड नहीं है। यानी एक साल से अधिक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान किस हाल में आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उनको किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, इस बारे में सरकार को कुछ पता ही नहीं है। क्या सरकार का सूचनातंत्र इतना कमज़ोर है कि सरकार को राजधानी की सीमा पर चल रहे आंदोलन की भी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। इससे पहले कोरोना काल में हुई मौतें के बारे में भी सरकार का यही अनजान रहने वाला चेहरा सामने आया था। चीन ने भारत की सीमा पर कहां तक अतिक्रमण किया इस बारे में भी सरकार ने चुप्पी साथ रखी थी। पेगासस जासूसी कांड पर भी सरकार कुछ नहीं कहना चाहती। आखिर देश मैं घट रही हर बात, जिस पर जनता परेशान है, उससे सरकार इतनी अनजान क्यों है। खैर, कृषि मंत्री का जवाब आधिकारिक तौर पर संसद में दर्ज हो गया है, तो मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा, ये अभी तय हो गया है। अब अगे इस मामले को अदालत में ले जाया जाए, तो बात अलग है। जब किसानों की मौत के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी ही नहीं है, तो ये बात भी तय है कि कोई स्पारक भी शहीद किसानों की याद में सरकार की ओर से नहीं बनेगा। वैसे भी सरकार यदि स्पारक और मुआवजे की बात मान लेगी तो यह उसकी विफलता को ही साबित करेगी। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, इसलिए सरकार का भी कोई गलती करना जुर्म नहीं है। मगर उस गलती को न मानना, अपनी विफलता को जुमलों और बादों के बोझ में दबा देना, ये गलत है। मोदी सरकार ने तो कृषि कानूनों की वापसी करते हुए भी यह नहीं माना कि इन कानूनों को पारित कर उसने कोई गलत काम किया है। सरकार की नजर में कानून सही हैं, उनका विरोध गलत है। लेकिन फिर भी कानून वापसी हुई तो यह उम्मीद बंधने लगी कि अब बाकी मार्गे भी सरकार मान लेगी। अभी सरकार ने एमसएपी के लिए भी किसान संगठनों से पांच नेताओं के नाम मार्गे हैं। आंदोलनकारी किसानों में से बहुत से लोग इसे भी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं। अब किसान संगठनों के बीच इस बात को लेकर विवर्श चल रहा है कि आंदोलन जारी रखा जाए या खत्म कर घर लौटा जाए। एक साल से अपने घरों और खेतों से दूर रहकर आंदोलन करना और हर रोज सरकार और सरकार समर्थकों की ओर से चली जा रही चालों का जवाब देना आसान नहीं है। ऐसे में आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटते हैं, तो आश्वय नहीं है। मगर इसके साथ ही सरकार की नीयत पर नजर रखना जरूरी है।

कृषि मंत्री ने तो मंगलवार को संसद में ये भी बताया था कि 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई है और पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या 5,579 रही है। जबकि एनसीआरबी के ही आंकड़े बताते हैं कि किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्या रुकने की बजाय बढ़ रही है। देश में 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में 10,677 लोगों की आत्महत्या की, इसमें 5,579 किसान और 5,098 खेतिहर मजदूरों की आत्महत्याएं शामिल हैं। दस हजार से अधिक लोगों ने जिंदा रहने की जगह मौत को गले लगाया, तो इसके पीछे जरूर बड़ी वजहें ही रही होंगी। मगर इन वजहों को जानने की जगह आंकड़ों के दम पर ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सरकार किसानों का भला चाहती है, लेकिन कुछ किसान इस बात को समझ ही नहीं रहे, तो फिर आगे कुछ कहने-समझने की गुंजाइश ही कहां रह जाती है। किसानों ने अपनी इच्छाशक्ति के बूते सरकार को कुछ झुकें पर तो मजबूर कर दिया है, मगर राजनीति के पेंचोखम में किसानों के हित उलझ कर न रह जाएं, यह देश को देखना होगा।

चिंताजनक है जीका वायरस का हमला

योगेश कमार गोयल

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही लगातार कमी देखी जा रही है लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामलों के साथ कुछ दिनों से जीका वायरस ने भी नई चिंता को जन्म दिया है। उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले जिस तेजी के साथ सामने आए हैं, उससे चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, मथुरा सहित कई जिलों में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं और अब फतेहपुर जिले में भी जीका वायरस का केस सामने आने के बाद वहां स्वास्थ्य विभाग में हड्डकंप मचा है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला तो जीका वायरस और डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहाँ जीका का पहला मामला 24 अक्टूबर को सामने आया था और उसके बाद से वहां पिछले करीब एक महीने में ही इसके 140 से भी अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। जीका संक्रमण को लेकर चिंताजनक स्थिति यह है कि यह वायरस सामान्य लोगों के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमित कर रहा है। अब तक कई गर्भवती महिलाएं जीका वायरस से संक्रमित मिल चुकी हैं। इस वर्ष जीका वायरस का पहला मामला केरल में 8 जुलाई 2021 को सामने आया था, जिसके बाद केरल में जीका वायरस के मामले अचानक सामने आने लगे और ऐसे मामलों की संख्या 64 तक पुंच गई थी। वहां जीका से एक मरीज की मौत की खबर सामने आई थी। महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का मामला सामने आया था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जीका का प्रकोप चिंता का

कांग्रेस को कमजोर कर बीजेपी से कैसे लड़ेंगी ममता

प्रेम कुमार

प्रेमकुमार

हैं वे जानते हैं कि ऐसा नहीं है। बंगाल में किसकी जीत हुई सच यह है कि जीत गैरकांग्रेसवाद की हुई। बीजेपी की ताकत तो वास्तव में बड़ी है कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गये, जो कभी गैरकांग्रेसवाद से लड़ाई नहीं थी। अक्सर एक-दूसरे के साथ हुआ करते थे। हालाँकि ऐसा दिखता जरूर नहीं कि बंगाल में जो चुनाव नतोंज सामने आए वह बीजेपी से लड़ाई के नाम पर ही आए। हास्यास्पद बात यह रही कि खुट कांग्रेस और लेफ्ट गैरकांग्रेसवाद की सियासत का ओजार बन गए। अब ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा के मायने समझें। ममता बनर्जी राष्ट्रीय सियासत में भी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस उसी भूमिका में रहे जिस भूमिका में बंगाल में दिखी थी। यानी बकरा बनकर हलाल हो कंग्रेस और उसका मीट बीजेपी से 'लड़ने वाले योद्धा' खाएं। क्या कांग्रेस बंगाल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बकरा बनकर लिए तैयार होगी?

सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं होने को इस पृष्ठभूमि में देखे जाने की जरूरत है। ममता ने खीज दिखलाई। फिर वह कांग्रेस ने बुग नहीं माना तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के तेवर देखको 'कांग्रेसमुक्त भारत' बनाने की कोशिश और विचार से लड़ने की है बीजेपी के हाथों सियासी रूप से कल्प होना कांग्रेस को मंजूर है लेकिन वह अपनी ही पैदाइश तृप्तमूल कांग्रेस के हाथों जबह होने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी-अखिलेश से सीख ले सकती हैं ममता-ममता बनर्जी की तेजस्वी और अखिलेश यादव से सीख लेनी चाहिए। दोनों दलों की सियासत में बीजेपी के मुकाबले गैरकांग्रेसवाद कभी हावी नहीं रहा। यूपी में पिछला चुनाव अखिलेश की सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हारा था। उसके बाद भी कांग्रेस से दूरी तो बड़ी लेकिन दुश्मनी हुई है ऐसा नहीं दिखता। बिहार में तेजस्वी यादव ने नुकसान झेलकर भी कांग्रेस के साथ मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा। एक सोच है कि अगर ओवैस फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी बिहार जीत लेते। क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर गैरकांग्रेसवाद की सियासत में असदृश्य ओवैसी होने जा रही है?

हैंजो दक्षिणपंथी सियासत के लिए 'जीवनदान' साबित होंगी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना गैरकांग्रेसवाद को बढ़ावा देना है और ऐसा करके राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प खड़ा नहीं किया जा सकता।

आज भी अखिलेश यादव कांग्रेस के बकरा बनाने की नहीं सोचते। तेजस्वी की भावी योजना में गैरकांग्रेसवाद नहीं है। धूर दक्षिणपंथी उद्घव ठाकरे की शिवसेना भी गैरकांग्रेसवाद को खारिज करने वाली सियासत कर रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार बहुत पहले मान चुके हैं कि कांग्रेस विरोध की सियासत वे भूल चुके हैं और पहले उन्होंने जो कुछ किया वह सही नहीं था। किसान आंदोलन को धार क्यों नहीं देतीं ममता-ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में सूत्रधार की भूमिका निभा सकती हैं मगर ऐसा कांग्रेस को कमज़ार करने की सियासत करते हुए नहीं हो सकता। एक टांग से बंगाल जीतने के बाद दोनों टांगों से देश जीतने की महत्वाकांक्षा सही है। मगर, इस महत्वाकांक्षा को मजबूत करने के लिए ममता को देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करना होगा। जाहिर है बंगाल से बाहर निकलना होगा। ममता बनर्जी चाहें तो किसान आंदोलन को धार दे सकती हैं। वह चाहें तो महंगाई पर देश में आंदोलन का नेतृत्व कर सकती हैं। वह चाहें तो पैगासस और केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों पर भी देश की सियासत की एक-सूत्र में पिरो सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आवाज बुलांद करके भी वह नई पहल कर सकती हैं। निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों पर भी ममता मुखर हो सकती हैं। मगर, इन मोर्चों पर वह सक्रिय नहीं हैं। अगर सियासत आंदोलन न होकर जोड़-तोड़ हो तो बीजेपी और बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश करने वाली पार्टी में फर्क ही क्या रह जाता है। सही मायने में देखा जाए तो ममता बनर्जी बीजेपी के बजाय कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए अधिक छटपटाती दिख रही हैं। इस मकसद में अगर वह सफल होती हैं तो वह निश्चित रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी को मिलने वाली सफलता से बीजेपी को मदद मिल जाया करती है। न ओवैसी कभी मुसलमानों का नेतृत्व कर पाए हैं और न ही ममता बनर्जी कभी गैर बीजेपीवाद की सियासत का नेतृत्व कर पाएंगी।

सवाल नजर और नजरिए का है

सर्वमित्रा सुरजन

पहल कराना काल म हुई मात्रा क बार म भी सरकार का यहा अनजान रहने वाला चेहरा सामने आया था। चीन ने भारत की सीमा पर कहां तक अतिक्रमण किया इस बारे में भी सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। पेगासस जास्सी कांड पर भी सरकार कुछ नहीं कहना चाहती। आखिर देश में घट रही हर बात, जिस पर जनता परेशान है, उससे सरकार इतनी अनजान क्यों है। खैर, कृषि मंत्री का जवाब आधिकारिक तौर पर संसद में दर्ज हो गया है, तो मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा, ये अभी तय हो गया है। अब आगे इस मापदण्ड को अदालत में ले जाया जाए, तो बात अलग है। जब किसानों की मौत के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी ही नहीं है, तो ये बात भी तय है कि कोई स्मारक भी शहीद किसानों की याद में सरकार की ओर से नहीं बनेगा। वैसे भी सरकार यदि स्मारक और मुआवजे की बात मान लेगी तो यह उसकी विफलता को ही साबित करेगी। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, इसलिए सरकार का भी कोई गलती करना जुर्म नहीं है। मगर उस गलती को न मानना, अपनी विफलता को जुमलों और वादों के बोझ में ढबा देना, ये गलत है। मोदी सरकार ने तो कृषि कानूनों की वापसी करते हुए भी यह नहीं माना कि इन कानूनों को पारित कर उसने कोई गलत काम किया है। सरकार की नजर में कानून सही है, उनका विरोध गलत है। लेकिन फिर भी कानून वापसी हुई तो यह उम्मीद बंधने लगी कि अब बाकी मार्गें भी सरकार मान लेगी। अभी सरकार ने एमसएपी के लिए भी किसान संगठनों से पांच नेताओं के नाम मार्गे हैं। आंदोलनकारी किसानों में से बहुत से लोग इसे भी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं। अब किसान संगठनों के बीच इस बात को लेकर विवर्षा चल रहा है कि आंदोलन जारी रखा जाए या खत्म कर घर लौटा जाए। एक साल से अपने घरों और खेतों से दूर रहकर आंदोलन करना और हर रोज सरकार और सरकार समर्थकों की ओर से चली जा रही चालों का जवाब देना आसान नहीं है। ऐसे में आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटते हैं, तो आश्वय नहीं। मगर इसके साथ ही सरकार की नीयत पर नजर रखना जरूरी है।

कृषि मंत्री ने तो मंगलवार को संसद में ये भी बताया था कि 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई है और पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या 5,579 रही है। जबकि एनसीआरबी के ही आंकड़े बताते हैं कि किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्या रुकने की बजाय बढ़ रही है। देश में 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में 10,677 लोगों की आत्महत्या की, इसमें 5,579 किसान और 5,098 खेतिहासी लोगों की आत्महत्या शामिल हैं।

किसान जर ३,०९८ खात्ती नगदों का जानलेपाए राजनीति। दस हजार से अधिक लोगों ने जिंदा रहने की जगह मौत को गले लगाया, तो इसके पीछे जरूर बड़ी वजहें ही रही होंगी। मगर इन वजहों को जानने की जगह आकड़ों के दम पर ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सरकार किसानों का भला चाहती है, लेकिन कुछ किसान इस बात को समझ ही नहीं रहे, तो फिर आगे कुछ कहने-समझने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। किसानों ने अपनी इच्छासत्ति के बूते सरकार को कुछ छुकने पर तो मजबूर कर दिया है, मगर राजनीति के पेंचोखम में किसानों के हित उलझ कर न रह जाएं, यह देश को देखना होगा।

जहां तक सवाल महिला अस्मिता और सम्मान का है, तो उस पर निरंतर संवाद और विमर्श की गुंजाइश देश में है, क्योंकि महिलाओं को पूरी तरह बराबरी का दर्जा मिलने के लिए अभी कई बड़े कदम उठाने बाकी हैं। संसद में महिला आरक्षण से ले कर धर-परिवार और समाज में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर सजगता से फैसले लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं के सामने इस क्षेत्र में अभी कई चुनौतियां हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत के साथ ही मुद्दों की तपिश बढ़ी शुरू हो गई है, लेकिन इनके साथ ही गैरजरूरी बातों पर भी माहौल को गरमाने की राजनीति दिखने लगी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों और अंग्रेजी के भारी-भरकम शब्दों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस बार एक सेलफी और उसके साथ लिखी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए। इस बार शीतकालीन सत्र के शुरू होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, पटियाला की सांसद परनीत कौर, दक्षिण चेन्नई की सांसद थमिजाची थांगपांडियन, जादवपुर की सांसद मिमी चक्रवर्ती, बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां और करूर से सांसद एस जोथिमनी के साथ संसद में ली गई एक सेलफी पोर्ट की। इस तस्वीर के साथ शशि थरूर ने कैप्शन दिया है कि- 'कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है आज सुबह मेरे साथी सांसदों के साथ।' शशि थरूर के साथ ली गई इस तस्वीर में उनके समेत छह महिला सांसद मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। यानी संसद में काम के बीच एक खुशगवार पल को इन साथी सांसदों ने तस्वीर में कैद कर लिया। अलग-अलग दलों के सांसदों का यूं एक साथ हसते-मुस्कुराते तस्वीर लेना, दरअसल भारतीय लोकतंत्र की विविधता भरी खुबसूरती का द्योतक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए, भिन्न विचारधारा और दलों के ये निर्वाचित प्रतिनिधि अलग-अलग होते हुए भी एक साथ मुस्कुरा सकते हैं, साथ काम कर सकते हैं और अपने संसदीय दायित्वों को निभा सकते हैं, इस तस्वीर का यह मतलब भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहां सवाल नजर और नजरिए दोनों का है। इसलिए शशि थरूर की इस तस्वीर पर अकारण विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। खासकर इस तस्वीर के साथ दिए गए कैप्शन को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है और इसे महिला विमर्श के साथ जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर शशि थरूर को ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा- 'महिलाएं आपके वर्कप्लैन्स को आकर्षक बनाने के लिए लोकसभा में सजाने की कोई वस्तु नहीं है। वे सांसद हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर आप

अन्य सेक्टर में होते तो आपको अट्रैक्टिव कहने के लिए निकाल दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने लिखा, अविश्वसनीय है कि किसी ने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि शशि थरूर ने निर्वाचित महिला नेताओं के सिर्फ लुक तक समीक्षा करने की कोशिश की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सहित कुछ नामचीन महिलाओं ने उस तस्वीर और टिप्पणी को अभद्र तथा थरूर की संकीर्ण सोच का परिचायक माना।

शान्ता विश्वास गोदेरा नाम से जापी शर्मा ने नारीन्द्र देवे द्वा-रा-

संसद में महिला आरक्षण से ले कर घर-परिवार और समाज में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर सजगता से फैसले लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं के सामने इस क्षेत्र में अभी कई चुनौतियाँ हैं। बाल विवाह, दहेज, यौन शोषण, छेड़छाड़, घर और कायास्थलों पर उत्पीड़न, भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, पुरुषों से कम वेतन मिलना, रक्षा खेल, पत्रकरिता, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के संघर्ष, विज्ञापनों में महिला की गरिमा को कम करने का चित्रण, ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं, जिन पर अगर सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएं दिन-रात काम करें, तब जाकर महिलाओं की स्थिति में थोड़े बहुत सुधार की उमीद हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह इस वक्त एक गैरजस्ती मुद्दे पर बहस में शक्ति व्यर्थ की जा रही है।

यह सही है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों को हमेशा सतर्क रहकर ही कोई टिप्पणी करना चाहिए। क्योंकि उनके कहे या लिखे का असर व्यापक होता है। लेकिन शाशि थरूर प्रकरण में यह साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने स्वस्थ भावना से कैषान लिखा, उसमें कोई गलत इरादे नहीं हैं। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने अपने शो केबीसी में आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के लिए कहा था कि 'इतना खूबसूरत चेहरा इनका, इकॉनामी के साथ कोई जोड़ ही नहीं सकता...' इस टिप्पणी को कई लोगों ने महिला विरोधी मानते हुए अमिताभ बच्चन की आलोचना की थी। हालांकि खुद गीता गोपीनाथ ने इस पर खुशी जताई थी कि सदी के महानायक बिंग बी की जबरदस्त प्रशंसक होने के नाते ये मेरे लिए खास है। वहां भी सवाल नजरिए का ही है। क्योंकि अमूमन अर्थशास्त्र को नीरस और बोझिल विषय माना जाता है और अर्थशास्त्री धीर-गंभीर मुद्रा में दिखते हैं। ऐसे में गीता गोपीनाथ के हंसते-मुस्कुराते चेहरे पर कहीं गई इस बात को गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। इससे पहले रघुराम राजन के आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा जा चुका है। हल्की-फुल्की टिप्पणियों को खुलेमन से ही सुना और समझा जाए, तो उसका आनंद उठाया जा सकता है। उन्हें सिद्धांतों और नैतिकता के खाने में जबरन डालने से उनका विद्रूप होना स्वभाविक है। अगर संसद में महिलाओं की बेहतरी, उनके सम्मान की फिक्र ही करना है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रेणुका चौधरी की हँसी की तुलना टीवी पर आने वाले रामायण के किरदार से की थी, उसे याद रखना चाहिए। हर बात को महिला विमर्श से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इससे महिला अधिकारों से जुड़े असल मुद्दे दब जाते हैं और महिला उत्पीड़न के खतरे और बढ़ जाते हैं। शायद अभी मीराई ने फूर्माया है-

कौन सी जा है जहाँ जल्वा-ए-माशूक नहीं,
शौक-ए-दीदार अगर है तो नजर पैदा कर

पश्चिम यूपी में किसकी चल रही है हवा

लगभग दो दशक बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित राष्ट्रीय लोक दल अपनी शर्तों पर चुनावी समझौता कर रहा है। आरएलडी का समाजवादी पार्टी से चुनाव समझौता लगभग तय हो चुका है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवाएं कुबल बदल गई हैं, जो आरएलडी इस कदर उत्साहित है और उससे चुनाव समझौता करने वाली एसपी भी। आगामी विधानसभा चुनाव को दृग्ख

न
र
पी
छ
पी
ते
व

के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए यह साफ दिखा था कि बीजेपी को शिकस्त दे पाना बहुत कठिन है। हालांकि जातीय समीकरणों की वृष्टि से विपक्षी दलों का वह सबसे मजबूत गठजोड़ था। फिर भी महागठबंधन से खड़े अंजित सिंह (मुजफ्फरनगर) और उनके पुत्र जयंत (बागपत) दोनों चुनाव हार गए थे। क्या इस बार गन्ना बेल्ट में किसान आंदोलन के असर और महंगाई जैसे मुद्दों के कारण आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ से बीजेपी मात्र खा जाएगी यह लाख टके

सनाजयपादा बाट के ठिठाड़ सभीजाना भारत खा जाएगा पर लाखोंटक का सवाल है और इसका उत्तर सभी तलाश रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि वे कौन से कारण थे कि विपक्षी दलों का मजबूत महागठजोड़ 2019 में बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सका था और वे कौन से कारक हैं जिनके आधार पर माना जाए कि बीजेपी इस बार अपनी मजबूत जमीन खो सकती है। कहा जा सकता है कि किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र बहुत है, मुस्लिम और जाट एकजुट हो गए हैं, इसलिए बीजेपी के लिए यह मैदान कठिन हो गया है। लेकिन जमीनी हकीकत तक पहुंचने पर इस आकलन में तमाम किंतु-परंतु लग जाते हैं। दलितों की संख्या की व्याप्ति से उर्वरा इस भूमि में इस बार बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में है और इसमें कोई दो राय नहीं कि दलितों का एक बड़ा वर्ग फिलहाल मायावती के साथ खड़ा दिखता है। 2019 में मायावती समर्थक मतदाताओं को लगता था कि इस बार उनकी नेता प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इसलिए वे एकजुट होकर महागठबंधन के साथ थे। इसके बावजूद परिणाम विपरीत आए। ऐसे में

इस बार जब दलित एसपी-आरएलडी गठजोड़ के साथ जाते नहीं दिख रहे हैं तो क्या यह गठजोड़ चमत्कार कर पाएगा

किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद सामाजिक समीकरण बदल गए थे। लेकिन गैर-बीजेपी दलों को लगता है कि अब जाटों और मुसलमानों के बीच ढूरी कम हुई है। जमीन पर यह दिखता भी है कि आपसी कटुता कम हुई है। किसान आंदोलन के नाम पर सभी एक साथ आए हैं। कुल मिलाकर, यह निश्चित है कि जाट मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी सरकार से नाराज है और वह आरएलडी की तरफ देख रहा है। सभी लोग इस विवरण सही समझ सकते हैं।

